



भाकृअनुप-कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान

जी.टी. रोड, रावतपुर, कानपुर – 208 002
(उत्तर प्रदेश)

An ISO 9001:2015 Certified

(O) : (0512) 2533560, 2554746
Fax : (0512) 2533560, 2554746
Website : <http://atarik.res.in>
E-mail : zpdicarkanpur@gmail.com

दि. 27-11-2020

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय प्रबन्ध कमेटी-IV की कार्यशाला

दि. 27 नवम्बर 2020 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखण्ड राज्य की क्षेत्रीय प्रबन्ध कमेटी की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसकी जानकारी भाकृअनुप-अटारी कानपुर निदेशक डा. अतर सिंह ने दी। कार्यशाला में पिछली कार्यशाला में निकले नतीजों और कार्य की स्थिति की समीक्षा की गई। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में श्री नरेन्द्र सिंह तोमर माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार ने कहा कि कृषि क्षेत्र में और प्रगति हो, और रोजगार उत्पन्न हों, नये कृषि क्षेत्र आयामों को छुए इस दिशा में भारत सरकार कार्य कर रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से कृषि शिक्षा के प्रचार प्रचार में अच्छा कार्य हो रहा है। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भाकृअनुप संस्थानों, कृषि विज्ञान केन्द्रों आदि के माध्यम से वैज्ञानिक कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करने में लगे हुए हैं। खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर हुए हैं जिसके लिये किसानों के परिश्रम के साथ कृषि विज्ञान केन्द्रों ने भी काफी योगदान दिया है। बागवानी, दुग्ध उत्पादन में भी भारत विश्व में पहले अथवा दूसरे नंबर पर दिखेगा। निर्यात में और कार्य करने की जरूरत है। इसके लिये नई निर्यात नीति भी बनाई गई है। कृषि में उत्पादन व उत्पादकता बढ़े यह लक्ष्य है। इसे प्राप्त करने में सफलता भी प्राप्त की है। हम उत्पादन केन्द्रित होने के साथ आय केन्द्रित भी बनें। छोटे रकबे में भी आय बढ़े। छोटे किसानों को तकनीकी सहयोग से देकर किसान उत्पादक समूह एवं तकनीक से जोड़ा है। भारत सरकार द्वारा 10,000 नये किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना की गई है। 1 लाख करोड़ रुपये की धनराशि इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु प्रदान की गई है। नये कृषि बिलों से भी किसानों की आय दोगुनी करने में तेजी मिलेगी। राज्य भी कन्धे से कन्धा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केन्द्र एक प्रत्येक जिले में सक्षम और योग्य यूनिट है। हम जानते हैं कि केवीक के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, भारत सरकार संसधान उपलब्ध करा रही है। राज्य के संसधान और कृषि विज्ञान केन्द्रों का ज्ञान किसानों तक पहुँचे। इसका प्रयत्न राज्य सरकारों के सहयोग से हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों से किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में तेजी से प्रयत्न किये जा रहे हैं। आज की कार्यशाला के माध्यम से आप सब से जो सुझाव आयेंगे और जो निष्कर्ष निकलेंगे उन पर कार्य किया जायेगा। पिछले बार के मात्र 14 रिकमण्डेशन शेष हैं जिन पर अभी काम चल रहा है।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सीड रिप्लेसमेन्ट रेट कम होने के कारण सीड रिप्लेसमेन्ट कम हो रही है। इस दिशा में विभागों के माध्यम से प्रयास किया गया है कि राज्य में सीड रिप्लेसमेन्ट रेट बढ़े। गत वर्षों में उ.प्र. में उत्पादकता काफी बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश को खाद्य उत्पादन में पुरस्कृत भी किया गया है। खाद्यान्न उत्पादन में

ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल की गई हैं। राज्य के किसानों का बोझ कम करने के लिये देनदारियाँ माफ की गई हैं। 2.20 करोड़ किसानों के खाते में धनराशि भेजने में हम सफल रहे हैं। फसल अवशेष प्रबन्धन में भी अच्छा कार्य हुए, धान के पुआल जलाने के केस कम देखने को मिले हैं। किसानों को मृदा परीक्षण कार्ड बांटे गये, प्रयास किया गया कि केमिकल्स का प्रयोग कम से कम हो। किसानों को किसान पाठशाला के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। 5-6 प्रतिशत ग्रोथ रेट बढ़ा है। हमने कोविड-19 में भी कृषि को रुकने नहीं दिया। साग सब्जियों, आम को बढ़े पैमाने पर निर्यात किया गया। बुन्देलखण्ड में खेत तालाब खोदे गये हैं। संसाधनों तकनीक को बढ़ाये जाने के लिये भी प्रयास किये गये हैं। विश्वविद्यालयों में नई भर्तियों के आदेश दे दिये गये हैं। चित्रकूट, गोण्डा व गोरखपुर द्वितीय केवीके का आधुनिकीकरण करने के लिये धनराशि उपलब्ध कराई गई है। मैं भाकृअनुप से आग्रह करता हूँ कि कृषि विश्वविद्यालयों को केवीके के लिये दी जा रही धनराशि में वृद्धि करें। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार में ए.आई.सी.आर.पी. बंद हो गये हैं उन्हें पुनः चलाने का मैं आग्रह करता हूँ। कुछ जिलों जैसे देवरिया, कुशीनगर, वाराणसी काफी बड़े हैं यहाँ 2 कृषि विज्ञान केन्द्रों की आवश्यकता है। कानपुर देहात और कानपुर नगर दो अलग-अलग जिले हैं परन्तु कानपुर नगर जिले में कोई भी कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं है, यहाँ कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता है। भाकृअनुप का राज्य के कृषि विभागों के साथ सामंजस्य हो। नई शिक्षा नीति 2020-21 में कई बदलाव हुए हैं उनमें वोकेशनल व तकनीकी शिक्षा में बदलाव भी है। अयोध्या, बांदा, मेरठ व कानपुर के राज्य कृषि विश्वविद्यालय काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं।

कार्यशाला में सचिव डेयर एवं महानिदेशक भाकृअनुप डा. त्रिलोचन महापात्रा जी ने आर.सी.एम. की संस्तुतियों की भाकृअनुप संस्थानों से समीक्षा ली। महानिदेशक महोदय ने कहा कि पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक फूड की माँग बढ़ी है। कोविड-19 की अवधि में भी 30 प्रतिशत से ज्यादा निर्यात हुआ इसके लिये सभी को बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी का आवाहन है कि 2022 तक आमदनी दोगुनी करनी है। इसमें अब अधिक समय शेष नहीं है। हमें 7500-1,00,000 किसानों की सफलता की कहानी का डाक्यूमेन्टेशन करना है जिससे 2022 में हम देश को बता सकें कि किस प्रकार हम किसानों की आमदनी दोगुनी करने में सफल हुए हैं। राज्य सरकारों की मदद से किसानों के पास तकनीक पहुँच रही है। 1 साल में डाक्यूमेन्टेशन होगा, जो कमियाँ रह जायेंगी उन्हें शेष समय में दूर करेंगे।

कार्यशाला में श्री नरेन्द्र सिंह तोमर माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार मुख्य अतिथि रहे। मा. केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला, सचिव डेयर एवं भाकृअनुप महानिदेशक डा. त्रिलोचन महापात्रा, सभी उपमहानिदेशक, सहायक महानिदेशक, भाकृअनुप संस्थानों के निदेशक, जोन III एवं IV के अटारी निदेशक, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति, कृषि सचिव एवं कृषि अधिकारी एवं अन्य वैज्ञानिकों सहित कुल 180 लोगों ने कार्यशाला में आनलाइन प्रतिभाग किया। उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव व निदेशकों ने तकनीकी ज्ञान की जानकारी भाकृअनुप से चाही।

उद्घाटन सत्र के समापन अवसर पर डा. ए.के. सिंह उपमहानिदेशक (कृषि प्रसार) ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया।



**ICAR-AGRICULTURAL TECHNOLOGY
APPLICATION RESEARCH INSTITUTE**
G.T. Road, Rawatpur, (Near Vikas Bhawan)
Kanpur – 208 002

☎(O) : (0512) 2533560
Fax : (0512) 2533560
Web site : <http://atarik.res.in>
E-mail :
zpdicarkanpur@gmail.com

(AN ISO 9001:2015 CERTIFIED ORGANIZATION)

Dated: 27.11.2020

ICAR Regional Management Committee-IV (UP, Bihar & Jharkhand)

On 27 November 2020, the Indian Council of Agricultural Research organized a Meeting of the Regional Management Committee of the states of Uttar Pradesh, Bihar and Jharkhand. Dr. Atar Singh, Director of ICAR-ATARI, Kanpur gave this information. In the meeting, the recommendations of the previous meeting and the status of action taken were reviewed. In the inaugural session of the workshop, Shri Narendra Singh Tomar, Hon'ble Minister of Agriculture, Government of India said that the Government of India is working in this direction to further progress in agriculture sector and generate employment. Through the Indian Council of Agricultural Research, good work is being done in the promotion of agricultural education. State agricultural universities, ICAR institutes, Krishi Vigyan Kendras' scientists are engaged in addressing the challenges of the agricultural sector. We have become self-sufficient in food grains, for which along with the hard work of the farmers, Krishi Vigyan Kendras have also contributed a lot. In horticulture, milk production too, India is in first or second position in the world. More work needs to be done in exports. A new export policy has also been prepared for this. This is the goal of increasing production and productivity in agriculture also succeeded in achieving this. We should be production oriented and income centric. Income also increased in small acreage. By giving technical support to small farmers, farmers have been associated with producer groups and technology. 10,000 new farmer producer organizations have been established by the Government of India. An amount of Rs 1 lakh crore has been provided for the infrastructure. New agricultural bills will also help in doubling the income of farmers. States are also collaborating. Krishi Vigyan Kendra is a competent unit in each district. We know that KVK does not have sufficient resources, Government of India is providing the resources. The state's resource and agricultural science centers should reach to the farmers. This should be done in collaboration with the State Governments. Efforts are being made in the direction of doubling the income of farmers with the instructions of Hon'ble Prime Minister. Through today's workshop, suggestions will come from all of you and conclusions will be drawn. There are only 14 recommendation of last time, which is still underway.

On this occasion, Agriculture Minister of Uttar Pradesh, Mr. Surya Pratap Shahi Ji said that in Uttar Pradesh, seed replacement is poor. In this direction, efforts have been made through the departments to increase the seed replacement rate in the state. UP in the last years Productivity has increased significantly. Uttar Pradesh has also been awarded by the Prime Minister in food production. Historical achievements have been made in food production. The liabilities have been waived to reduce the burden of the farmers of the

state. We have been successful in sending money to the account of 2.20 crore farmers. Crop residue management also did good work, cases of paddy straw burning have been less. Soil test cards were distributed to farmers, efforts were made to minimize the use of chemicals. Farmers were informed about various schemes through Kisan Pathshala. Growth rate has increased by 5-6 percent. We also did not allow agriculture to stop at Covid-19. Vegetables, mangoes were exported on a large scale. Farm ponds have been dug in Bundelkhand. Efforts have also been made to increase resource technology. New recruitments have been ordered in universities. Funds have been provided to modernize Chitrakoot, Gonda and Gorakhpur II KVKs from RKVY. I urge the ICAR to increase the funds being given to KVKs to agricultural universities. AICRP in the SAUs, I urge them to run again. Some districts like Deoria, Kushinagar, Varanasi are quite big and need 2 agricultural science centers. Kanpur Dehat and Kanpur Nagar are two separate districts, but there is no agricultural science center in Kanpur Nagar district, there is a need to establish Krishi Vigyan Kendra here. The ICAR should be harmonized with the agricultural departments of the state. There have been many changes in the new education policy 2020-21, among them there are changes in vocational and technical education. The State Agricultural Universities of Ayodhya, Banda, Meerut and Kanpur are doing very well.

In the meeting, Secretary DARE and Director General ICAR Dr. Trilochan Mohapatra ji. The recommendations of the IMC presented by IIVR, Varanasi, institute were reviewed from ICAR institutes. The Director General said that the demand for organic food has increased throughout the world. Congratulations to all for the export of more than 30 percent during the period of Covid-19. The call of Hon'ble Prime Minister is that by 2022, the income has to double. There is not much time left in this. We have to document the success story of farmers so that in 2022 we can tell the country how we have been able to double the income of farmers. Technology is reaching farmers with the help of state governments. Documentation will happen in 1 year, the deficiencies that remain will be removed in the remaining time.

Shri Narendra Singh Tomar, Honorable Minister of Agriculture & Farmers welfare, Government of India was the Chief Guest, Union Minister of State for Agriculture & Farmers welfare Shri Purushottam Rupala, Secretary DARE and Director General of ICAR, Dr. Trilochan Mohapatra, All Deputy Director General, Assistant Director General, Director of ICAR institutes, ICAR-ATARI Director of Zone III & IV, Vice Chancellor of State Agricultural Universities, Agriculture Secretary and Agriculture Officer from all three states, total of 180 people including scientists participated in the workshop online. Secretary and Directors of Uttar Pradesh Government required information about technical knowledge from ICAR.

In the ending of inauguration session, Dr. A.K. Singh Deputy Director General (Agricultural Extension) extended vote of thanks to everyone.

